अवीक सरकार और अन्य

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 902/2004)

फरवरी 03, 2014

[के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. सिकरी जे.जे.]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा.482 -

कार्यवाही को रद्द करते हुए-जर्मन पत्रिका ने विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी की तस्वीर के साथ एक लेख प्रकाशित किया, नग्न होकर अपने हाथों से अपने अश्वेत चमड़ी वाले मंगेतर के स्तन को ढंकना, जो फोटो उसके पिता के अलावा किसी और ने नहीं खींचें-दंपति ने रंगभेद के खिलाफ बात की और घोषणा की कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं है-लेख भारतीय पत्रिका और समाचार पत्र में पुन: प्रकाशित किया गया-पत्रिका और समाचार पत्र के संपादक और प्रकाशक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292, और महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986- की धाराएं 3, 4 और 6 के तहत कार्यवाही की । अपील पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने की घोषणा की, माना गया: यह तय करते समय कि क्या कोई विशेष तस्वीर, कोई लेख

या पुस्तक अश्लील है या नहीं, समकालीन मूल्यों और राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि अतिसंवेदनशील या संवेदनशील व्यक्तियों के समूह के मानक को।-हिकलिन परीक्षण "अश्लीलता क्या है" निर्धारित करने के लिए लागू होने वाला सही परीक्षण नहीं है-उन सेक्स-संबंधित सामग्रियों की प्रवृत्ति होती है "रोमांचक वासनापूर्ण विचार" को अश्लील माना जा सकता है, हालांकि, अश्लीलता को एक औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए, समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करके-उक्त चित्र को उस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जिसमें यह दिखाया गया था, और यह संदेश बड़े पैमाने पर जनता और दुनिया को बताना है-यह संदेश जो समाज में नस्लवाद और रंगभेद की बुराई को मिटाता है और प्यार और शादी को बढ़ावा देता है श्वेत चमड़ी वाले आदमी और एक अश्वेत चमड़ी वाली महिला के बीच-जब अंतर देखा जाता है उस कोण, चित्र या लेख को आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कार्यवाही शुरू करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 या अंतर्गत अधिनियम, 1986 की धारा 4-मजिस्ट्रेट, पृष्ठभूमि की सराहना के बिना जिसमें तस्वीर दिखाई गई थी, अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव – न्याय के हितो को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा अंतर्गत 482 महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धाराएं 3,4,6 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत

अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया -

जर्मन पत्रिका ने विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी (बोरिस) की तस्वीर के साथ एक लेख प्रकाशित किया, नग्न होकर अपने हाथों से अपने काली चमड़ी वाले मंगेतर (बारबरा) के स्तन को ढंकना, जो उसके पिता के अलावा किसी और ने नहीं देखा था. दंपति ने रंगभेद के खिलाफ खुलकर बात की और घोषणा की कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं है लेख में कहा गया है कि तस्वीर का उद्देश्य भी नफरत पर उस प्रेम चैंपियन को इंगित करने के लिए थी. इस लेख को "स्पोर्ट्स वर्ल्ड" में पुनः प्रकाशित किया गया था, जो भारत में प्रकाशित एक व्यापक रूप से प्रसारित पत्रिका है और फिर एक अखबार आनंदबाज़ार पत्रिका कोलकाता में व्यापक प्रचलन में है ।

कोलकाता के एक वकील ने अपीलकर्ताओं, संपादक और अखबार के प्रकाशक और मुद्रक के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई. साथ ही स्पोर्ट्स वर्ल्ड के संपादक के खिलाफ शिकायत में कहा गया है कि नग्न तस्वीर इस देश के बच्चों और युवाओं दोनों को युवा दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए प्रभाव डालने वाला था और हमारे समाज के नैतिक मूल्यों और संस्कृति के खिलाफ था । जब तक कि इस तरह की अश्लील तस्वीरों को प्रतिबंधित

और बंद नहीं किया जाता है और आरोपी व्यक्तियों को दंडित नहीं किया जाता है, तब तक हमारी नारीत्व की गरिमा और सम्मान खतरे में होगा। शिकायतकर्ता ने यह भी आग्रह किया कि आरोपी व्यक्तियों पर न केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, बल्कि महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986- की धारा 4 के तहत मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए । क्योंकि फोटो प्रथम दृष्टया एक यौन शीर्षक देता है और इसका प्रभाव नैतिक पतन है और यह लोगों को यौन अपराध करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा । मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया एक मामला माना। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सम्मन जारी किया ।

5.3.1993 को आरोपी व्यक्तियों ने कार्यवाही को रद्द के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया था कि खेल जगत के साथ-साथ आनंदबाज़ार पत्रिका में समाचार को पुन: प्रकाशित करने में कोई अवैधता नहीं थी । आनंदबाज़ार पत्रिका और तस्वीर जर्मनी में प्रकाशित एक पत्रिका 'STERN' में दिखाई दी । इसके अलावा, यह बताया गया कि उक्त पत्रिका को कभी भी भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और इसे कभी भी‘ ’ , खासकर जब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 79 का प्रावधान कहता है -किसी भी व्यक्ति द्वारा कानूनन किया गया कार्य अपराध नही है, जो तथ्य की गलती के कारण किया गया है और अच्छे विश्वास में कानून की गलती का कारण नहीं है।

मजिस्ट्रेट ने आरोपी व्यक्तियों की जांच दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के तहत की और आदेश दिया कि उन्हें अपराध के मुकदमे का सामना करने के लिए रखा जाएगा । महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत वैकल्पिक रूप से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत दंडनीय माना। अपीलकर्ताओं ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय से पहले, यह बताया गया था कि मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य की ठीक से विवेचना नहीं की थी कि भारत में जर्मन खेल पत्रिका 'STERN' के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं था । परिणामतः किसी भी तस्वीर का पुनः प्रकाशन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 79 में निहित सामान्य अपवाद के भीतर होगा । तस्वीर का उल्लेख करते हुए, यह बताया गया कि तस्वीर ने केवल टेनिस खिलाड़ी द्वारा दर्ज किए गए विरोध का प्रदर्शन किया खिलाड़ी के साथ-साथ ' रंगभेद "के खिलाफ उनके मंगेतर और उन तथ्यों को मजिस्ट्रेट द्वारा ठीक से विवेचन नहीं गया । इसके अलावा, यह भी बताया गया कि तस्वीर को अश्लील या अपमानजनक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रत्येक नग्नता अश्लील नहीं होती और चित्र किसी भी तरीके से न तो कामुक था और न ही उत्तेजक और सामान्य रूप से युवाओं या जनता के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर

दिया जिसके खिलाफ तत्काल अपील को प्राथमिकता दी गई थी ।

न्यायालय ने अपील स्वीकार की:

अश्लीलता और सामुदायिक मानकों का परीक्षण

अभिनिर्धारित:

1.1 वर्ष 1965 में संविधान बेंच ने रंजीत डी. उदेशी में निधार्रित किया कि अश्लीलता की अवधारणा समय बीतने के साथ बदल जाएगी और एक समय में "अश्लील" क्या हो सकता है जो बाद की अवधि में अश्लील माना जाता है । निर्णय में अश्लीलता की धारणा बदलने के कई उदाहरणों को संदर्भित किया गया है । वर्ष 1969 में, चंद्रकांत कल्याणदास काकोदर में न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि भारत में समकालीन समाज के मानक भी तेजी से बदल रहे हैं । समकालीन सामुदायिक मानकों और सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत को एस. खुशबू [पैरा 12, 13, 14] [2- ए-बी, डी, एफ] 2010 में फिर से दोहराया गया।

1.2 रंजीत डी. उदेशी में न्यायालय ने प्रकाश डाला शब्द, चित्र, पेंटिंग, आदि में छूट दी जाने वाले नाजुक कार्य को पारित करने में न्यायालयों द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 और न्यायालय के तहत अश्लीलता का परीक्षण यह बताता है कि दंड संहिता अश्लील शब्द को और इस नाजुक कार्य को परिभाषित नहीं करता है कि कैसे भेद किया जाए उसके बीच जो कलात्मक है और जो अश्लील है । अदालतों द्वारा, और

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम उपाय में परीक्षण किया जाना है । परीक्षण स्पष्ट रूप से एक सामान्य चरित्र का होना चाहिए, लेकिन यह सीमांकन की एक पंक्ति को इंगित करने के लिए मामले से मामले में एक उचित आवेदन को स्वीकार करना चाहिए जरूरी नहीं कि तेज हो लेकिन भेद करने के लिए पर्याप्त रूप से अलग हो उसके बीच जो अश्लील है और जो नहीं है अब तक किसी ने भी अश्लीलता की परिभाषा का प्रयास नहीं किया है इस अर्थ को बिना किसी परिभाषा के प्रयास के बिना रखा जा सकता है, जिसका वर्णन करना चाहिए । हालाँकि, यह एक बार में कहा जा सकता है कि कला और साहित्य में सेक्स और नग्नता के साथ व्यवहार करना बिना कुछ और के अश्लीलता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है । अश्लीलता का परीक्षण हमारे संविधान के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुरूप होना चाहिए । यह अदालत को एक सबसे दूरगामी चरित्र के संवैधानिक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करता है और यह सावधान रहना चाहिए कि यह गारंटीकृत स्वतंत्रता से बहुत दूर नहीं झुक सकता है । इस परीक्षण को लागू करते हुए, "लेडी चटरलीज लवर" पुस्तक के लिए, रंजीत डी. उदेशी में न्यायालय ने यह माना कि सेक्स के साथ-साथ लगाए गए भागों को अलग-अलग देखा गया और पूरी किताब की व्यवस्था से हमारे सामुदायिक मानकों से आंका गया था और किताब भी निर्धारित सीमा पार कर गई वहाँ जनता के लिए कोई सामाजिक लाभ नहीं है जिसे कहा जा सकता है कि पुस्तक को पूर्व निर्धारित करने के लिए

अश्लीलता के परीक्षण को पूरा करने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। [पैरा 15, 16] [278-एफ-एच; 279-ए-ई]

1.3 उपन्यास "लेडी चटरलीज लवर्स" जिसे इस न्यायालय द्वारा अश्लील के रूप में निंदा गया था सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा इंग्लैंड में अश्लील नहीं माना गया। इंग्लैंड में, अश्लीलता का सवाल जूरी पर छोड़ दिया जाता है । यह मामला वर्ष 1994 का है, लेकिन अब 2014 है और यह देखते हुए कि क्या कोई विशेष तस्वीर, एक लेख या पुस्तक अश्लील है, संबंध समकालीन मूल्यों और राष्ट्रीय मानकों के लिए होना चाहिए न कि अतिसंवेदनशील या संवेदनशील व्यक्तियों के समूह के मानक। [पैरा 17, 19] [279-एफ; 281-एफ]

समरस बोस बनाम अमल मित्रा (1985) 4 एससीसी 289: 1985 (3) सप्ल. एससीआर 17; एस खुशबू बनाम कनिअम्मल (2010) 5 एससीसी 600: 2010 (5) एससीआर 322; रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1965 एससी 881: 1970 (2) एससीआर 80; चंद्रकांत कल्यांण दास काकोदर बनाम महाराष्ट्र राज्य 1969 (2) एससीसी 687: 1970 (2) एससीआर 80-पर निर्भर ।

आर. वी. पेंगुइन बुक्स लि. (1961 अापराधिक कानून की समीक्षा 176-को संदर्भित किया गया ।

हिकलिन टेस्ट:

2. यूनाइटेड किंगडम में 1868 में वापस कोर्ट ने रेजिना बनाम हिकलिन में हिकलिन परीक्षण किया. हिकलिन परीक्षण ने प्रकाशित किया कि एक प्रकाशन को संदर्भ से बाहर माने जाने वाले कार्य के अलग-अलग मार्ग के आधार पर अश्लीलता के लिए आंका जाना चाहिए और जैसे बच्चे या कमजोर दिमाग वाले वयस्क सबसे अतिसंवेदनशील पाठकों पर उनके स्पष्ट प्रभाव से आंका जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, हालांकि, एक चिह्नित प्रस्थान बना दिया । देर से, यह महसूस किया कि अश्लीलता क्या है, यह निर्धारित करने के लिए हिकलिन परीक्षण सही परीक्षण नहीं है । रोथ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपवाद के रूप में अश्लीलता के मुद्दे सीधे निपटाए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोर्ट ने वह आयोजन किया "अश्लीलता" की अस्वीकृति पहले संशोधन में निहित थी । यह देखते हुए कि सेक्स और अश्लीलता को एक-दूसरे का पर्याय नहीं माना जाता था, कोर्ट ने कहा कि केवल उन सेक्स-संबंधित सामग्रियों में जो "रोमांचक वासनापूर्ण विचारों" की प्रवृत्ति पाई गई अश्लील और उसी को समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करके एक औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए । कनाडा में भी, बहुमत ब्रॉडी बनाम द क्वीन में आयोजित किया गया कि डी.एच. लॉरेंस का उपन्यास "लेडी चटरलीज लवर" कनाडाई आपराधिक संहिता के अर्थ के भीतर अश्लील नहीं था । रेजिना में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय बनाम बटलर ने माना कि प्रमुख परीक्षण "सामुदायिक मानकों की

समस्याओं का परीक्षण" है" । न्यायालय ने उस स्पष्ट सेक्स को रखा जो हिंसक नहीं है और न ही अपमानजनक है और न ही अमानवीय आमतौर पर कनाडा में सहन किया जाता है । समाज और सेक्स के अनुचित शोषण के रूप में योग्य नहीं होगा जब तक कि वह अपने उत्पादन में बच्चों को शामिल नहीं करता है । न्यायालय ने कार्य या सामग्री को 'अश्लील' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आयोजित किया, सेक्स शोषण का न केवल एक प्रमुख विशेषता होनी चाहिए, बल्कि इस तरह के शोषण को "अनुचित" होना चाहिए" । इससे पहले टाउन सिनेमा थिएटर लिमिटेड बनाम द क्वीन, में कैनेडियन कोर्ट ने सामुदायिक मानक परीक्षण लागू किया न कि हिकलिन परीक्षण। [पैरा 20-23] [281-जी; 282-बी-एच; 283-ए]

ब्रॉडी बनाम द क्वीन 1962 एससीआर 681; रेजिना बनाम बटलर (1992) 1 एससीआर 452; टाउन सिनेमा थियेटर्स लिमिटेड बनाम द क्वीन (1985) 1 एससीआर 494-पर भरोसा किया ।

रेजिना बनाम हिकलिन (1868 एल.आर. 2 क्यू. बी. 360); रोथ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 354 यू.एस. 76 (1957) परीक्षण करने के लिए भेजा ।

सामुदायिक मानकों का परीक्षण

3. "अश्लीलता क्या है" यह निर्धारित करने के लिए हिकलिन परीक्षण सही परीक्षण नहीं है"। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 निश्चित रूप से

अभिव्यक्ति 'आकर्षक और व्यावहारिक' का उपयोग करता है हितों या इसके प्रभाव का बाद में, इसमें भी संकेत दिया गया है प्रभाव की प्रयोज्यता की उक्त धारा और वस्तुओं को समग्र रूप से और उस नींव पर ले जाने की आवश्यकता जहां इस तरह की वस्तुओं को नष्ट करना और भ्रष्ट करना होगा संभावना है, सभी के संबंध में प्रासंगिक परिस्थितियाँ, इसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने के लिए । इसलिए, "समुदाय अश्लीलता परीक्षण " क्या है, यह निर्धारित करने के लिए "हिकलिन परीक्षण" के बजाय मानक परीक्षण "लागू किया जाना है" । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के उप खंड एक पढ़ने से स्पष्ट होगा कि एक तस्वीर या लेख को अश्लील माना जाएगा

(i) यदि यह कामुक है;

(ii) यह विवेकपूर्ण हित के लिए अपील करता है, और

(iii) यह उन लोगों को अपमानित और भ्रष्ट करता है, जो इस मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं, जो अश्लील होने का आरोप लगाते हैं । एक बार जब मामला अश्लील पाया जाता है, तो यह सवाल उठ सकता है कि क्या लगाया गया आरोप किसी के भीतर आता है \ जैसे कि अनुभाग में निहित अपवादों की एक नग्न / अर्ध-नग्न महिला की एक तस्वीर, अश्लील नहीं कहा जा सकता है जब तक कि यह एक अति यौन इच्छा को महसूस करने या प्रकट करने की प्रवृत्ति न हो । चित्र को

मन को उकेरने का सुझाव दिया जाना चाहिए और इसे उत्तेजित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए उन व्यक्तियों में यौन जुनून जो इसे देखने की संभावना रखते हैं, जो विशेष मुद्रा और पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा जिसमें नग्न / अर्ध-नग्न महिला को दर्शाया गया है । केवल उन सेक्स संबंधी सामग्रियों की प्रवृत्ति होती है, जिनमें "आकर्षक विचारों को व्यक्त करना अश्लील होने के लिए आयोजित किया जा सकता है, लेकिन समकालीन समुदाय को लागू करके अश्लीलता को एक औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए। [पैरा 24] [283-बी-जी]

संदेश और संदर्भ

4. सामुदायिक सहनशीलता परीक्षण को लागू करना, तस्वीर अवसादग्रस्त मन और विचारोत्तेजक नहीं है यौन उत्तेजना के लिए डिज़ाइन किया गया उन व्यक्तियों में जुनून जो उन्हें देखने और उन्हें देखने की संभावना रखते हैं, जो विशेष मुद्रा और पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा जिसमें महिला को चित्रित या दिखाया गया है । बारबरा फुल्टस का स्तन पूरी तरह से बोरिस बेकर की बांह से ढका हुआ था, ज़ाहिर है कि फोटोग्राफ अर्ध-नग्न था, लेकिन उसके पिता के अलावा किसी और ने नहीं लिया । इसके अलावा, तस्वीर में उन लोगों के दिमाग को हटाने या भ्रष्ट करने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी जिनके हाथों में पत्रिका स्पोर्ट्स वर्ल्ड या आनंदबाजार पत्रिका में गिरावट आ जायेगी । उक्त चित्र को प्रकाशित करने के पीछे

उद्देश्य है की चित्र को उस पृष्ठभूमि में देखा जाए जिसमें इसे दिखाया गया था, और यह संदेश जनता और दुनिया को बड़े पैमाने पर बताना है । पत्रिका की कवर स्टोरी जर्मनी में नस्लवाद से जूझते हुए, नग्न होकर, उत्पीड़न को छोड़ने का शीर्षक प्रस्तुत करती है । जर्मन पत्रिका में प्रकाशित लेख में खुद बोरिस बेकर ने जर्मनी में प्रचलित नस्लीय भेदभाव की बात की और इस लेख ने जर्मनी में नस्लवाद के खिलाफ उनके विरोध को उजागर किया । तस्वीर संदेश व्यक्त करना चाहती है कि त्वचा का रंग पर बहुत कम और प्रेम का दर्जा रंग से उपर मायने रखता है । चित्र प्रेम संबंध को बढ़ावा देता है, एक शादी के लिए अग्रणी, एक सफेद चमड़ी वाले आदमी और एक अश्वेत चमड़ी वाली महिला के बीच। इसलिए, संदेश के प्रकाश में तस्वीर और लेख जो इसे व्यक्त करना चाहता था, वह है समाज में नस्लवाद और रंगभेद की बुराई को मिटाना और बढ़ावा देना सफेद चमड़ी वाले पुरुष और एक काली चमड़ी वाली महिला के बीच प्यार और शादी को । जब उस कोण में देखा जाता है, तो चित्र या लेख जिसे स्पोर्ट्स वर्ल्ड और आनंदबज़ार पत्रिका द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया था, आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता ताकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत या महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत कार्यवाही शुरू की जा सके । अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के तहत नही किया गया था और फिर यह सवाल अध्ययनीय हो गया है कि क्या यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा

79 के पहले भाग में आता है। मजिस्ट्रेट ने मन के उचित अनुप्रयोग या पृष्ठभूमि की सराहना के बिना जिसमें तस्वीर दिखाई गई थी, अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। जिस स्थिति में उन्होंने अपीलकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने का आदेश नहीं दिया होगा, उस स्थिति में न्यायिक मिसालों के आधार पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए था। उच्च न्यायालय के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 न्याय के हितो को सुरक्षित करने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही अलग रखी गई है। [पैरा 27-31] [285-डी-एच; 286-बी-जी]

बॉबी आर्ट इंटरनेशनल ओर अन्य बनाम ओम पाल सिंह हून (1996) 4 एससीसी 1: 1996 (2) सप्ल. एससीआर 136; अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ (2007) 1 एससीसी 143: 2006 (10) सप्ल. एससीआर 770- पर निर्भर किया।

संदर्भ निर्णीत वाद:

1970 (2) एससीआर 80	पैरा 10	पर निर्भर था
1970 (2) एससीआर 80	पैरा 10	पर निर्भर था
1985 (3) सप्ल. एससीआर 17	पैरा 14	पर निर्भर था
2010 (5) एससीआर 322	पैरा 14	पर निर्भर था

1962 एससीआर 681	पैरा 22	पर निर्भर था
(1992) 1 एससीआर 452	पैरा 22	पर निर्भर था
(1985) 1 एससीआर 494	पैरा 23	पर निर्भर था
196 (2) सप्ल. एससीआर 136	पैरा 25	पर निर्भर था
2006 (10) सप्ल. एससीआर 770	पैरा 26	पर निर्भर था:

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 902/2004

कलकत्ता में उच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 1591/1994 के निर्णय आदेश दिनांकित 17.03.2004 से।

प्रदीप घोष, अमर दवे, अभिषेक रॉय और कार्तिक भटनागर (मानिक करंजवाला के लिए) अपीलकर्ताओं के लिए।

मोहित पॉल, शगुन मटका, (एनीप सचथे के लिए), वी.डी. खन्ना उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था।

के.एस. राधाकृष्णन, जे.

1. दुनिया भर में प्रचलन वाले "STERN" नाम से एक जर्मन पत्रिका ने एक विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर की तस्वीर के साथ एक लेख प्रकाशित किया, जो एक फिल्म अभिनेत्री बारबरा फेल्टस नाम से अपने अश्वेत चमड़ी वाले मंगेतर के साथ नग्न फोटो खिंचवाई गई थी जहाँ

उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था। लेख में कहा गया है कि, एक साक्षात्कार में, बोरिस बेकर और बारबाबा फेल्टस दोनों ने अपनी सगाई के बारे में खुलकर बात की, उनके जीवन और भविष्य की योजनाएं और संदेश जो वे बड़े पैमाने पर लोगों को बताना चाहते थे, ऐसी तस्वीर के लिए लेख में बोरिस बेकर को "रंगभेद" के खतरनाक अभ्यास के एक स्पष्ट रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है" । इसके अलावा, यह कहा गया था कि तस्वीर का उद्देश्य घृणा पर उस प्रेम चैंपियन को इंगित करना भी था।

2. भारत में 05.05.1993 को लेख और तस्वीर के साथ एक व्यापक रूप से प्रसारित पत्रिका "स्पोर्ट्स वर्ल्ड", प्रकाशित हुई इसके अंक 15 में शीर्षक के साथ एक कहानी को कवर के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया ।

> "जर्मनी में नस्लवाद से जूझते हुए, टूर्नामेंट से बाहर निकलने के लिए नग्न पोज़ देना. बोरिस बेकर जीवन के लिए अपने हालिया दृष्टिकोण की व्याख्या करते हैं। "- बोरिस बेकर

अनमाक्सड

3. कोलकाता में व्यापक प्रचलन वाले एक समाचार पत्र, आनंदबाज़ार पत्रिका, अखबार के दूसरे पृष्ठ में उपर्युक्त तस्वीर के साथ-साथ 06.05.1993 के लेख में भी प्रकाशित हुआ, जैसा कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में दिखाई दिया।

4. अलीपुर जज कोर्ट, कोलकाता में अभ्यास करने वाला एक वकील, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के नियमित पाठक होने का दावा करने के साथ-साथ आनंदबाजार पत्रिका ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, संपादक और अखबार के प्रकाशक और मुद्रक के साथ-साथ स्पोर्ट्स वर्ल्ड के संपादक, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, पटौदी के दिवंगत मंसूर अली खान, अलीपुर में उप-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से पहले शिकायत में कहा गया है जैसा कि एक अनुभवी एडवोकेट और एक बुजुर्ग व्यक्ति, वह कर सकता था। वाउचर ने कहा कि नग्न तस्वीर आनंदबाज़ार पत्रिका में दिखाई दी, साथ ही साथ स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, इस देश के बच्चों और युवाओं दोनों को युवा दिमाग भ्रष्ट करेगा, और हमारे समाज के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब तक इस तरह की अश्लील तस्वीरों को सेंसर और प्रतिबंधित और आरोपी व्यक्ति दंडित नहीं किया जाता है, हमारी नारीत्व की गरिमा और सम्मान खतरे में होगा। शिकायतकर्ता को अन्य बातों के साथ, 10.5.1993 को न्यायालय के समक्ष भी भेजा गया, निम्नानुसार है:

> "..... कि अभियुक्त नंबर 1 और अभियुक्त नंबर 2 दोनों आनंद बाजार पत्रिका और स्पोर्ट्स वर्ल्ड के संपादकों ने जानबूझकर अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए अभियुक्त नंबर 3 की मदद से, विशेष रूप से उनके कागजात और

पत्रिकाओं की बिक्री के लिए प्रकाशित, मुद्रित और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित और प्रसारित और अपने कागजात और पत्रिकाओं को भी बेच दिया, अर्थात्, आनंद बाजार पत्रिका और स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने 6.5.1993 दिनांकित किया, जिसमें विश्व स्तर के लॉन टेनिस खिलाड़ी की तस्वीर थी, बोरिस बेकर और उनकी प्रेमिका जर्मन फिल्म अभिनेत्री मिस बारबरा को एक अंतर-जुड़वां तरीके से प्रकाशित किया गया है जिसमें बोरिस बेकर ने मिस बारबरा के स्तन पर हाथ रखा है जो एक शीर्षक के साथ मेरी याचिका में संलग्न है ' बोरिस बैकर बेपर्दा जो प्रकृति में बिल्कुल अश्लील और कामुक है और जो एक आपराधिक अपराध है। अश्लील और नग्न तस्वीरों के समाज में प्रकाशित होने से आरोपी व्यक्तियों द्वारा खुद के साथ-साथ विभिन्न आयु वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।"

5. विद्वान मजिस्ट्रेट ने 10.5.1993 को 1993 के आपराधिक मामले के संदर्भ मामले संख्या सी 796 में निम्नलिखित आदेश पारित किया शिकायतकर्ता मौजूद है। उसकी जांच की जाती है और उसे मुक्त किया जाता है। कोई अन्य अभियोग पक्ष के गवाह मौजूद नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रथम दृष्टया मामला आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ

" भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत बनाया गया है। सभी आरोपियों ओर एस. पी. के खिलाफ दिनांक 17.6.1993 को उपस्थित अपेक्षित होने का समन जारी किया गया।"

6. शिकायतकर्ता ने यह भी आग्रह किया कि आरोपी व्यक्तियों पर न केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, बल्कि महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत मुकदमा चलाया जाए, फोटो प्रथम दृष्टया एक यौन उत्तेजना देता है और इसका प्रभाव नैतिक गिरावट है और यह लोगों को यौन अपराध करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। 5.3.1993 को आरोपी व्यक्तियों ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया था कि खेल जगत के साथ-साथ आनंदबाज़ार पत्रिका में भी कोई अवैधता नहीं थी समाचार और तस्वीर जर्मनी कि एक पत्रिका 'STERN' में प्रकाशित हुई। इसके अलावा, यह बताया गया कि उक्त पत्रिका पर कभी भी भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया था और इस पर कभी विचार नहीं किया गया था जैसा कि' ', खासकर जब भारतीय दंड संहिता की धारा 79 में कहा गया है कि कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कानून द्वारा उचित है, या जो तथ्य की गलती के कारण और अच्छे विश्वास में किया

जाता है कानून की गलती का कारण नहीं है, ऐसा करने में विश्वास करता है खुद को कानून द्वारा उचित ठहराया जा सकता है ।

7. तस्वीरों को देखने और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है: -

> "इसके अलावा, जब तक सबूत नहीं आते हैं, आरोपी व्यक्तियों की जिम्मेदारी के रूप में कोई राय देना उचित नहीं होगा । लेकिन मुझे यह उल्लेख करना उचित लगता है कि हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 292 शब्द 'अश्लील' को परिभाषित नहीं करती है, लेकिन मेरे छापे मिसाल के तौर पर इस बिंदु पर गोल-गोल घूम रहे हैं और रिकॉर्ड पर सामग्री से संतुष्ट हैं, उन लोगों के दिमाग को खंगालने और नष्ट करने में तस्वीर का खतरनाक प्रभाव जिनके हाथों में यह आ सकता है और अन्य पर्याप्त कारणों से आगे बढ़ने के लिए इस न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में प्रक्रिया जारी को रखा । वर्तमान में के संबंध में मामले के तथ्य, मुझे लगता है कि प्रार्थना के अनुसार कार्यवाही न रोककर मामला हस्तक्षेप के योग्य है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि आरोपी व्यक्ति

भारतीय दंड संहिता की धारा 79 का लाभ पाने के हकदार हैं ।"

8. ऐसा करने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के तहत जांच के लिए रखा और आदेश दिया कि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए रखा जाएगा वैकल्पिक रूप से महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत रखा जाएगा ।

9. अपीलकर्ताओं ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कलकत्ता के उच्च न्यायालय के समक्ष 1994 के आपराधिक संशोधन संख्या 1591 को प्राथमिकता दी। 1993 के प्रकरण नंबर 796 में कार्यवाही को रद्द करने के लिए (टी. आर. के अनुरूप 1994 का नंबर 35) विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, अलीपुर के समक्ष लंबित है । उच्च न्यायालय से पहले, यह बताया गया था कि मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य की ठीक से विवेचना नहीं की थी कि भारत में जर्मन खेल पत्रिका 'STERN' के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं था । परिणामतः किसी भी तस्वीर का पुनः प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 79 में निहित सामान्य अपवाद के भीतर होगा। संदर्भ था 20 जुलाई, 1993 को पत्र द्वारा भी संबोधित किया गया असिस्टेंट एडिटर, स्पोर्ट्स वर्ल्ड टू द कलेक्टर, कलकत्ता कस्टम्स और डिप्टी कलेक्टर,

कलकत्ता कस्टम्स द्वारा सहायक संपादक, स्पोर्ट्स वर्ल्ड को भेजे गए पत्र की एक प्रति चित्र का उल्लेख करते हुए, यह बताया गया कि चित्र केवल बोरिस बेकर द्वारा दर्ज किए गए विरोध प्रदर्शन के साथ-साथ उनके मंगेतर के खिलाफ 'रंगभेद' का प्रदर्शन करता है" और उन तथ्यों को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ठीक से विवेचन नहीं किया गया । आगे की, यह भी बताया गया कि अपमानजनक तस्वीर को अश्लील अस्मिता के रूप में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि नग्नता अश्लील नहीं थी और तस्वीर किसी भी तरीके से न तो कामुक थी और न ही उत्तेजक थी और सामान्य रूप से युवाओं या जनता के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसके अलावा, यह भी बताया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट को आवेदन के बिना सम्मन जारी नहीं करना चाहिए था । उच्च न्यायालय, हालांकि, उन सभी सामग्रियों की विवेचना नहीं की और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 483 के तहत कार्यवाही से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ इस अपील को प्राथमिकता दी गई है ।

10. श्री प्रदीप घोष, वरिष्ठ वकील, अपीलकर्ताओं के लिए प्रश्न प्रस्तुत किया कि प्रकाशन के साथ-साथ ली गई तस्वीर, एक पूरे और तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि के प्रति "अश्लील" नहीं कहा जा सकता है" भारतीय दंड संहिता की धारा 291 (1) के अर्थ के भीतर भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (1) के तहत कथित अपराध के संबंध में अपीलकर्ताओं के परीक्षण का रिमांड किया जा सके । विद्वान वकील ने बताया कि अश्लीलता को समकालीन सामाजिक मेलों, सह, प्रतिरक्षा के

वर्तमान सामाजिक-नैतिक रवैये और स्वीकार्यता के प्रचलित मानदंडों के संदर्भ में आंका जाना है। मुद्दे में मामलों के संबंध में समुदाय की संवेदनशीलता है । इस विवाद के समर्थन में निर्भरता रखी गई थी रंजीत डी. उदेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1965 SC 881 में इस न्यायालय का संविधान बेंच निर्णय। चंद्रकांत कल्याणदास काकोदर बनाम महाराष्ट्र राज्य 1969 (2) एससीसी 687। में इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था । उनके विवाद के समर्थन में कुछ अन्य निर्णयों को भी संदर्भित किया गया था । विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ मजिस्ट्रेट ने भी उस संदर्भ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जिसमें तस्वीर प्रकाशित की गई थी और यह संदेश जनता को"

यह भी बताया कि तस्वीर किसी भी तरह से अशिष्ट या कामुक नहीं है । वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के दायरे की ठीक से व्याख्या नहीं की है और अपीलकर्ताओं को तस्वीर और लेख प्रकाशित करने में कानून के लिए उचित ठहराया गया है जिसे जर्मन पत्रिका से उधार लिया गया था । वरिष्ठ वकील ने भी बताया कि इस तरह के प्रकाशन को कभी भी राज्य के अधिकारियों द्वारा अश्लील नहीं पाया गया था और कभी भी कोई एफआईआर नहीं हुई थी । अपीलकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई और इस तरह की प्रकृति की एक निजी शिकायत को तथ्यों के साथ-साथ कानून की

व्याख्या किए बिना विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मनोरंजन नहीं किया जाना चाहिए था । वरिष्ठ वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए ।

11. श्री मोहित पॉल, विद्वान वकील, उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित, प्रस्तुत किया गया है कि नीचे दिए गए न्यायालयों की राय को यह मानने में उचित ठहराया गया था कि आरोपी व्यक्तियों की दोषिता के रूप में एक राय देना उचित नहीं होगा जब तक कि उन्हें परीक्षण के लिए नहीं रखा जाता है और साक्ष्य जोड़ा जाता है । विद्वान वकील ने बताया कि यह सवाल कि क्या तस्वीर का प्रकाशन उचित है या नहीं और अच्छे विश्वास में बनाया गया था, अपीलकर्ताओं द्वारा साबित करने की आवश्यकता है क्योंकि अच्छे विश्वास और सार्वजनिक भलाई तथ्य के प्रश्न हैं और सबूत के लिए मायने रखता है । वकील की तलाश की बताया कि विद्वान मजिस्ट्रेट के साथ-साथ उच्च अदालत ने शिकायत को खारिज नहीं करने और अपीलकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने का आदेश देने के लिए उचित ठहराया था ।

अश्लीलता और सामुदायिक मानकों का परीक्षण

12. रंजीत डी. उदेसी में वर्ष 1965 में इस न्यायालय की संविधान बेंच. (Supra) संकेत दिया कि अश्लीलता की अवधारणा समय बीतने के साथ बदल जाएगी और क्या हो सकता है कि एक समय में "अश्लील" हो,

बाद की अवधि में अश्लील नहीं माना जाएगा । निर्णय संदर्भित करता है अश्लीलता की धारणा बदलने के कई उदाहरण और अंततः न्यायालय ने निम्नानुसार देखें: -

> "…. दुनिया, अब पूर्व की तुलना में बहुत अधिक सहन करने में सक्षम है, विभिन्न प्रकार के साहित्य द्वारा अनिश्चित है । रवैया अभी तक तय नहीं हुआ है.. ।"

इस न्यायालय ने वर्ष 1965 में यही कहा है ।

13. वर्ष 1969 में फिर से चंद्रकांत कल्याणदास काकोदर (Supra), में इस न्यायालय ने सिद्धांत को इस प्रकार दोहराया: -

> "भारत में समकालीन समाज के मानक भी तेजी से बदल रहे हैं ।"

14. उपर्युक्त सिद्धांत को दोहराया गया है समरेश बोस बनाम अमल मित्रा (1985) 4 एससीसी 289 में समकालीन सामाजिक मूल्यों और सामान्य पाठक के सामान्य रवैये पर जोर दिया । 2010 में एस. खुशबू बनाम कनिअम्मल (2010) 5 एससीसी 600 में समकालीन सामुदायिक मानकों और सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत को दोहराया गया है।

15. रंजीत डी. उदेशी में यह कोर्ट (Supra) ने यह देखते हुए कि क्या शब्द, चित्र, पेंटिंग, नाजुक कार्य को उजागर किया आदि को देखते हुए

न्यायालयों द्वारा अनुतोष दे दिया गया । न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत अश्लीलता का परीक्षण इस प्रकार होगा:

> "दंड संहिता अश्लील शब्द को परिभाषित नहीं करती है और इस बीच अंतर करने का यह नाजुक कार्य जो कलात्मक है और जो अश्लील है उसे अदालतों द्वारा और अंतिम उपाय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है । परीक्षण स्पष्ट रूप से एक सामान्य चरित्र का होना चाहिए लेकिन यह होना चाहिए मामले से मामले के लिए एक उचित आवेदन का स्वीकार करना एक सीमांकन की एक पंक्ति को इंगित करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त रूप से अलग है जो अश्लील है या नहीं है । अब तक किसी ने भी परिभाषा का प्रयास नहीं किया है अश्लीलता के कारण क्या देखना चाहिए, इसका वर्णन करके परिभाषा का प्रयास किए बिना अर्थ नहीं रखा जा सकता है । हालाँकि, यह एक बार में कहा जा सकता है कि कला और साहित्य में सेक्स और नग्नता के साथ कुछ और के बिना अश्लीलता के सबूत के रूप में व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अश्लीलता का परीक्षण हमारे संविधान के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ होना चाहिए । यह अदालत को एक सबसे दूरगामी

चरित्र के संवैधानिक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करता है और सावधान रहना चाहिए कि यह गारंटीकृत स्वतंत्रता से बहुत दूर तक झुकाव नहीं होना चाहिए। "

16. उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, न्यायालय ने "लेडी चटरलीज लवर्स" पुस्तक के लिए, रंजीत डी. उदेसी में (Supra) में सेक्स के साथ व्यवहार किए गए भागों को अलग-अलग देखा गया और पूरी पुस्तक की स्थापना में हमारे सामुदायिक मानकों से निर्धारित अनुमेय सीमा को पारित किया गया और कोई सामाजिक लाभ नहीं हुआ जिसे पहले से कहा जा सकता है अश्लीलता के परीक्षण को संतुष्ट करने के लिए पुस्तक का सार्वजनिक आयोजन किया जाना चाहिए।

17. उपन्यास "लेडी चटरलीज लवर्स" जिसे इस न्यायालय द्वारा अश्लील के रूप में निंदा गया था, को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा इंग्लैंड में अश्लील नहीं माना गया था । इंग्लैंड में, अश्लीलता का सवाल जूरी पर छोड़ दिया गया । बायरन, जे।, विद्वान न्यायाधीश जिन्होंने आर. बनाम पेंगुइन बुक्स लिमिटेड. (1961 आपराधिक कानून की समीक्षा 176) में केंद्रीय आपराधिक न्यायालय की अध्यक्षता की । निम्नानुसार देखी गई: -

"संक्षेप में उनके आधिपत्य ने जूरी को निर्देश दिया कि वे पुस्तक को समग्र रूप से विचार करना चाहिए, यहां और वहां मार्ग का चयन नहीं करना चाहिए और जमीन पर

अपने पैर रखना चाहिए, प्रकाशन के बाद पहला सवाल था: परीक्षण या सेंसर के कार्यों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्या पुस्तक अश्लील थी? क्या इसका प्रभाव पूरी तरह से वंचित और भ्रष्ट व्यक्तियों के रूप में लिया गया था, जिनकी संभावना थी सभी परिस्थितियों के संबंध में, इसे पढ़ने के लिए, नैतिक रूप से खराब करने के लिए, विकृत करने के लिए, बहस करने या नैतिक रूप से भ्रष्ट करने के लिए भ्रष्ट करने का मतलब नैतिक रूप से अस्वस्थ या सड़े हुए को प्रस्तुत करना, नैतिक शुद्धता या शुद्धता को नष्ट करना, एक अच्छी गुणवत्ता को बिगाड़ना या बर्बाद करना, अपवित्र करना है । कोई इरादा नहीं अवक्षेपण या भ्रष्ट आवश्यक था । मात्र तथ्य यह है कि जूरी को झटका लग सकता है और पुस्तक से घृणा करने से प्रश्न हल नहीं होगा । लेखकों को खुद को व्यक्त करने का अधिकार था लेकिन मजबूत विचारों वाले लोग अभी भी थे समुदाय के सदस्य और दूसरों के दायित्व के तहत उन्हें नैतिक, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से नुकसान न पहुंचाएं । दुनिया के पुरुषों और महिलाओं के रूप में जूरी विवेकपूर्ण नहीं है, लेकिन उदार दिमाग के साथ, खुद से पूछना चाहिए कि पुस्तक की प्रवृत्ति इसे पढ़ने की संभावना को कम और भ्रष्ट करने की थी, न केवल कुछ

शैक्षणिक संस्थान के दुर्लभ वातावरण में मार्गदर्शन के तहत पढ़ने वाले, लेकिन यह भी कि जो लोग थ्री शिलिंग और सिक्स पेंस के लिए पुस्तक खरीद सकते हैं या इसे सार्वजनिक पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं, संभवतः लॉरेंस के किसी भी ज्ञान के बिना और साहित्य के कम ज्ञान के साथ यदि जूरी उचित संदेह से परे संतुष्ट थे कि पुस्तक अश्लील थी, तो उन्हें विचार करना चाहिए हित में जनता की भलाई के लिए उचित होने का प्रश्न विज्ञान, साहित्य, कला या सीखने या सामान्य चिंता के अन्य विषय । साहित्यिक गुण पुस्तक को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसे जनता की भलाई के लिए उचित ठहराया जाना चाहिए । पुस्तक को अन्य के साथ तुलना करके आंका नहीं जाना था । पुस्तकें यदि यह अश्लील था, तो यदि प्रतिवादी ने इस संभावना को स्थापित किया है कि पुस्तक की योग्यता एक उपन्यास इतना ऊंचा था कि उन्होंने अश्लीलता को असंतुलित कर दिया ताकि प्रकाशन जनता का भला हो तो जूरी को बरी करना चाहिए । "

18.बाद में, समरेश बोस (Supra) में इस न्यायालय ने, समरेश बोस द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास "प्रजापति" का जिक्र करते हुए, निम्नानुसार मनाया: -

"35. ..... हम किताब पढ़ने से संतुष्ट नहीं हैं इसे अश्लील माना जा सकता है । एक चुंबन के संदर्भ, शरीर का वर्णन और पुस्तक में महिला पात्रों के आंकड़े और कृत्यों के सुझाव स्वयं के द्वारा सेक्स करने से किसी भी उम्र के पाठकों को हतोत्साहित करने, बहस करने और प्रोत्साहित करने का प्रभाव नहीं हो सकता है और इन गणनाओं पर उपन्यास, को अश्लील नहीं माना जा सकता है । यह सच है कि पुस्तक में स्लैंग और विभिन्न अपरंपरागत शब्दों का उपयोग किया गया है । हालांकि सेक्स के किसी भी ओवर एक्ट का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेक्स कृत्यों के सुझाव हैं और यह कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न लोगों के बीच व्यक्तियों के जीवन में सेक्स के पहलू पर बहुत जोर दिया गया है लोगों का स्तर उपन्यास में पाया जाना हैं । उपयोग की गई भाषा के कारण, उपन्यास में सुनाई गई यौन जीवन के संबंध में एपिसोड अशिष्ट दिखाई देते हैं और घृणा और विद्रोह की भावना पैदा कर सकते हैं । मात्र तथ्य यह है कि सेक्स पर जोर देने वाले विभिन्न मामलों और प्रकरणों को कठबोली और अशिष्ट भाषा में सुनाया गया है, एक पाठक

को झटका दे सकता है जो पुस्तक से घृणा महसूस कर सकता है अश्लीलता का सवाल है ।"

हमने पहले ही संकेत दिया है, यह वर्ष 1985 में समकालीन मानक था ।

19. हम इस मामले में, वर्ष 1994 की स्थिति से संबंधित हैं, लेकिन हम 2014 में हैं और यह देखते हुए कि क्या एक विशेष तस्वीर, एक लेख या पुस्तक अश्लील है, संबंध को समकालीन तटों और राष्ट्रीय मानकों के लिए होना चाहिए और अतिसंवेदनशील या संवेदनशील व्यक्तियों के समूह का मानक नहीं ।

हिकलिन टेस्ट:

20. यूनाइटेड किंगडम में, 1868 में वापस, कोर्ट रेजिना बनाम हिकलिन (1868 एल.आर. 2 क्यू.बी.360), में हिकलिन परीक्षण रखा और निम्नानुसार आयोजित:-

"अश्लीलता का परीक्षण यह है कि मामले की क्या प्रवृत्ति है अश्लीलता के रूप में आरोपित उन लोगों को वंचित और भ्रष्ट करना है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं और जिनके हाथों में इस तरह का प्रकाशन आ सकता है ।"

21. हिकलिन परीक्षण ने पोस्ट किया कि एक प्रकाशन संदर्भ से बाहर माने जाने वाले कार्य के अलग-अलग अंशों के आधार पर होना चाहिए । अश्लीलता के लिए न्याय किया जाता है और उनके द्वारा स्पष्ट न्याय किया जाता है अधिकांश अतिसंवेदनशील पाठकों पर प्रभाव, जैसे कि बच्चे या कमजोर दिमाग वाले वयस्क । हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, एक चिह्नित प्रस्थान किया देर से यह महसूस किया कि अश्लीलता क्या है, यह निर्धारित करने के लिए हिकलिन परीक्षण सही परीक्षण नहीं है । रोथ बनाम. संयुक्त राज्य अमेरिका 354 संयुक्त राज्य 476 (1957), में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपवाद के रूप में अश्लीलता के मुद्दे से सीधे निपटा । न्यायालय ने माना कि "अश्लीलता" की अस्वीकृति प्रथम संशोधन में निहित थी । यह देखते हुए कि सेक्स और अश्लीलता को एक-दूसरे का पर्याय नहीं माना जाता है, न्यायालय ने कहा कि केवल उन सेक्स-संबंधी सामग्रियों में "भद्दे विचारों को उकसाने" की प्रवृत्ति थी" अश्लील पाए गए और समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करके एक औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसी को आंका जाना चाहिए ।

22. ब्रॉडी बनाम द क्वीन (1962 एससीआर 681) में भी कनाडा में बहुमत से निर्णीत किया गया कि डी.एच. लॉरेंस का उपन्यास "लेडी चटरलीज लवर" कनाडाई आपराधिक संहिता के भीतर अश्लील नहीं था ।

23. रेजिना में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय बनाम बटलर (1992) 1 एससीआर 452, ने माना कि प्रमुख परीक्षण "सामुदायिक मानकों की समस्याओं का परीक्षण" है" । न्यायालय ने उस स्पष्ट सेक्स को रखा जो हिंसक नहीं है और न ही अपमानजनक है और न ही अमानवीय आमतौर पर कनाडाई समाज में सहन किया जाता है और जब तक यह बच्चों को रोजगार नहीं देता तब तक सेक्स के अनुचित शोषण के रूप में योग्य नहीं होगा । इसके उत्पादन में न्यायालय ने कार्य या सामग्री के लिए 'अश्लील' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, सेक्स का शोषण न केवल एक प्रमुख विशेषता होनी चाहिए, बल्कि इस तरह के शोषण को "अनुचित" होना चाहिए". इससे पहले टाउन सिनेमा में थियेटर्स लिमिटेड बनाम द क्वीन (1985) 1 एससीआर 494, कनाडाई कोर्ट ने सामुदायिक मानक परीक्षण लागू किया न कि हिकलिन परीक्षण।

समुदाय मानक परीक्षण:

24. हमारा यह भी विचार है कि हिकलिन परीक्षण सही नहीं है "अश्लीलता क्या है" निर्धारित करने के लिए लागू किया जाने वाला सही परीक्षण" नहीं है । भारतीय दंड संहिता की धारा 292, निश्चित रूप से अभिव्यक्ति 'आकर्षक और विवेकपूर्ण हितों' या इसके प्रभाव का उपयोग करती है । बाद में, यह प्रभाव की प्रयोज्यता के उक्त खंड में भी इंगित किया गया है और वस्तुओं को समग्र रूप से और उस नींव पर ले जाने की

आवश्यकता है जहां इस तरह की वस्तुएं होती हैं वंचित और भ्रष्ट व्यक्ति, जो संभावना रखते हैं, सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के संबंध में, इसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने के लिए । इसलिए, हमें "हिकलिन परीक्षण" के बजाय "सामुदायिक मानक परीक्षण" लागू करना है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि "अश्लीलता" क्या है" । धारा 292 की उपधारा (1) में, यह स्पष्ट करता है कि किसी चित्र या लेख को अश्लील माना जाएगा (i) यदि वह कामुक है; (ii) यह विवेकपूर्ण हित के लिए अपील करता है, और (iii) यह उन लोगों को अपमानित और भ्रष्ट करता है, जो इस मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं, जो अश्लील होने का आरोप लगाते हैं । एक बार मामला अश्लील पाया जाता है यह सवाल उठ सकता है कि क्या धारा में निहित किसी भी अपवाद के भीतर लगाया गया मामला है । की एक तस्वीर एक नग्न या अर्ध-नग्न महिला, जैसे कि, उसे अश्लील नहीं कहा जा सकता है जब तक कि यह एक अति यौन इच्छा को महसूस करने या प्रकट करने की प्रवृत्ति न हो । चित्र को मन को उकेरने का सुझाव दिया जाना चाहिए और यौन उत्तेजना के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए उन व्यक्तियों में जुनून जो इसे देखने की संभावना रखते हैं, जो उस पर निर्भर करेगा विशेष मुद्रा और पृष्ठभूमि पर जिसमें नग्न या अर्ध-नग्न महिला को दर्शाया गया है । केवल उन सेक्स-संबंधित सामग्रियों में "उत्तेजित वासनापूर्ण विचारों" की प्रवृत्ति होती है, जिन्हें अश्लील माना जा सकता है, लेकिन समकालीन सामुदायिक मानकों

को लागू करके अश्लीलता को एक औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए ।

संदेश और संपर्क

25. हमें उस संदर्भ में अश्लीलता के प्रश्न की जांच करनी होगी जिसमें तस्वीर दिखाई देती है और यह संदेश बताना चाहता है । बॉबी आर्ट इंटरनेशनल व अन्य बनाम ओम पाल सिंह हून (1996) 4 एससीसी 1, में बैंडिट क्वीन नामक फिल्म के संदर्भ में अश्लीलता के सवाल से निपटने के दौरान इस न्यायालय ने बताया कि फिल्म में तथाकथित आपत्तिजनक दृश्यों को संदेश का संदर्भ में माना जाना चाहिए कि फिल्म एक असहाय महिला बच्चे के खिलाफ अत्याचार और हिंसा के सामाजिक खतरे के संबंध में संचारित करना चाहती थी उसे एक खूंखार डकैत में बदल दिया । न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया: -

> "सबसे पहले, वह दृश्य जहां उसे अपमानित किया जाता है, नग्न कर अपमानित किया जाता है, एक सौ पुरुषों के घेरे के भीतर, परेड किया जाता है कुएं से पानी खींचने के लिए बनाया जाता है. उन पुरुषों के लिए उसके स्तनों और योनी के संपर्क का उद्देश्य उन लोगों द्वारा किया जाता है जो उसे नीचा दिखाने के लिए पीटा करते हैं । उस पर इतने ज़ुल्म के प्रभाव को स्पष्ट रूप से बेहतर तरीके से

व्यक्त किया जा सकता था दृश्य दिखा रहा है । इसका उद्देश्य सिनेमाओ की वासना को शांत करना नहीं था, बल्कि पीड़ित के प्रति सहानुभूति और ओरो के लिए घृणा पैदा करना था । ट्रिब्यूनल ने जो विद्रोह का उल्लेख किया, वह फूलन देवी की नग्नता पर नहीं था, बल्कि उन लोगों के दुख और हृदयहीनता पर था गरिमा के हर टुकड़े को लूटने के लिए उसे नग्न कर दिया था । नग्नता हमेशा निम्न मानसिकता को उत्तेजित नहीं करती है । द ट्रिब्यूनल द्वारा फिल्म "शिंडलर्स लिस्ट" का संदर्भ उपयुक्त था । इसमें नग्न पुरुषों और महिलाओं की पंक्तियों का एक दृश्य है, जिसे सामने दिखाया गया है, एक नाजी एकाग्रता शिविर के गैस कक्षों में ले जाया जा रहा है । न केवल वे मर जाते हैं लेकिन उनके अंतिम क्षणों में मनुष्य की मूल गरिमा को छीन लिया गया है । आँसू एक संभावित प्रतिक्रिया है; दया, डरावनी और शर्म की एक साथी-भावना निश्चित है, केवल उस बिगाड़ को छोड़कर जो उत्तेजित हो सकता है । हम बिगाड़ने की रक्षा करने या अति-संवेदनशील की संवेदनशीलता को आत्मसात करने के लिए सेंसर नहीं करते हैं । "बैंडिट क्वीन" एक शक्तिशाली मानव कहानी बताती है और उस कहानी के लिए फूलन देवी की नग्न परेड का दृश्य

केंद्रीय है । यह समझाने में मदद करता है कि फूलन देवी क्यों बनीं, उस पर आक्रोश था उन्होंने क्या किया: उनके गुस्से और प्रतिशोध ने उस समाज को प्रभावित किया।

[इम्फेसिस सप्लाईड]

26. अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ (2007) 1 SCC 143, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 और अनुभागों के दायरे की जांच करते हुए महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 4 और 6, के तहत इस न्यायालय ने माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता मांग करती है कि इसे दबाया नहीं जा सकता, जब तक कि इसके द्वारा बनाई गई परिस्थितियां स्वतंत्रता को दबाने की अनुमति नहीं देती हैं और सामुदायिक हित खतरे में है ।

27. हमें यह जांचना होगा कि बोरिस बेकर की तस्वीर उनके मंगेतर बारबरा फुल्टस के साथ है या नहीं, एक काले रंग की चमड़ी वाली महिला एक-दूसरे के करीब खड़ी होती है, लेकिन अपने मंगेतर के स्तन को अपने हाथों से ढंकना इस अर्थ में आपत्तिजनक कहा जा सकता है कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 292 का उल्लंघन करता है । सामुदायिक सहिष्णुता परीक्षण को लागू करते हुए, हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि इस तरह की तस्वीर अवसादग्रस्त दिमाग की विचारोत्तेजक है और इसे उत्तेजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । उन व्यक्तियों में यौन

जुनून जो उन्हें देखने और उन्हें देखने की संभावना रखते हैं, जो उस विशेष मुद्रा और पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा जिसमें महिला को चित्रित किया गया है या दिखाया गया । बारबरा फुल्टस का स्तन पूरी तरह से बोरिस बेकर की बांह के साथ कवर किया गया है, एक तस्वीर, निश्चित रूप से, अर्ध-नग्न, लेकिन बारबरा के पिता के अलावा कोई नहीं लिया गया । इसके अलावा, हमारे विचार में, तस्वीर में उन लोगों के दिमाग को हटाने या भ्रष्ट करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है जिनके हाथों में पत्रिका स्पोर्ट्स है दुनिया या आनंद बाजार पत्रिका गिर जाएगी।

28. हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि उक्त चित्र को उस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जिसमें यह दिखाया गया था, और यह संदेश बड़े पैमाने पर जनता और दुनिया को बताना है । पत्रिका की कवर स्टोरी जर्मनी में नस्लवाद से जूझते हुए, नग्न होकर, उत्पीड़न को छोड़ने को शीर्षक प्रस्तुत करती है । बोरिस बेकर खुद जर्मन पत्रिका में प्रकाशित लेख में, जर्मनी में प्रचलित नस्लीय भेदभाव की बात करते हैं और लेख जर्मनी में नस्लवाद के खिलाफ बोरिस बेकर के विरोध को उजागर करता है. बोरिस बेकर खुद इसे कहते हैं, जैसा कि उक्त लेख में उद्धृत किया गया है: "नग्न तस्वीरे चौकाने वाली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है..... मैं इन तस्वीरों के साथ जो कह रहा हूं वह यह है कि एक अंतर-नस्लीय संबंध ठीक है।"

29. संदेश, तस्वीर यह बताना चाहती है कि त्वचा का रंग बहुत कम मायने रखता है और रंग से अधिक प्यार करता है । एक सफेद चमड़ी वाला आदमी और काली चमड़ी वाली औरत का चित्र प्रेम संबंध को बढ़ावा देता है, ओर एक विवाह के लिए अग्रणी है।

30. इसलिए, हमें उस संदेश के प्रकाश में फोटोग्राफ और लेख की सराहना करनी चाहिए जिसे वह व्यक्त करना चाहता है, यह समाज में नस्लवाद और रंगभेद की बुराई को खत्म करने और सफेद चमड़ी वाले आदमी और एक काली चमड़ी वाली महिला के बीच प्यार और शादी को बढ़ावा देने के लिए है । जब उस दृष्टिकोण में देखा जाता है, हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि चित्र या लेख जिसे स्पोर्ट्स वर्ल्ड और आनंद बाजार पत्रिका द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया था, को आपत्तिजनक कहा जा सकता है ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 292 या महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत कार्यवाही शुरू की जा सके ।

31. हमने पाया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत कोई अपराध बनना नहीं पाया गया है और फिर यह सवाल है कि क्या यह भारतीय दंड संहिता की धारा 79 का पहला भाग में आता है । हमें खेद है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने, न्यायिक मस्तिष्क या पृष्ठभूमि की सराहना के बिना जिसमें तस्वीर दिखाई गई है, में अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन

कार्यवाही शुरू की । विद्वान मजिस्ट्रेट को न्यायिक प्रावधानों के संबंध में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए था उस स्थिति में उसने अपीलार्थियों को मुकदमे का सामना करने के लिए आदेश नहीं दिया होता। हमारे विचार में उच्च न्यायालय द्वारा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

32. इसलिए हम इस अपील को स्वीकार कर अपीलार्थियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को अपास्त किया जाता है । उपरोक्तानुसार अपील स्वीकार की जाती है ।

डी. जी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महावीर सिंह चारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।